

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशुराम धानका, आ.ए.एस.

अपील संख्या:- 99/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)

तारीख रज्जू 10.07.2017

आरसीएमएस संख्या :- 2017/00190

उनवान

1. भूपसिंह पुत्र श्री खुशीराम जाति जाट निवासी पुरानी पत्थर की टाल अनाह गेट जिला भरतपुर -राज0 । (मृतक)

1/1 घनश्याम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह

1/2 पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह

1/3 टोनी कुमार सोगरवाल पुत्र श्री मानसिंह

1/4 लोकेश पुत्र श्री मानसिंह

1/5 खैमसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह

1/6 कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह

1/7 सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह

1/8 चेतन सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह

1/9 राजवीरी पुत्री भूपसिंह पत्नी जगवीर सिंह जाति जाट निवासी अनाह गेट बजरिया

1/10 मिथलेश पुत्री भूपसिंह पत्नी खजानसिंह जाति जाट निवासी अनाह गेट बजरिया

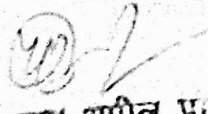
जाति जाट निवासी अनाह गेट बजरिया
भरतपुर - राजस्थान

.....अपीलांत ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर।
3. नगर परिषद भरतपुर जरिये अध्यक्ष ,नगर परिषद भरतपुर

..... रैसपोडेंटस


अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरुद्ध निर्णय एवं डिफ्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 12.05.2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 17/2013 उनवानी भूपसिंह बनाम राज0 सरकार वगै0।

उपरिस्थित :-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महाराजसिंह डागुर

निर्णय

28.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य विरुद्ध है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बरान 483, 484, 486, 487, स्थित ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में कृषि कार्य हेतु आने-जाने के लिए 30 फुट चौड़ा कदीमी रास्ता हमेशा से हाल खसरा नम्बर 485 गत 223 /3-13 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे स्थित रहा है। जिसके उत्तरी भाग में होकर मथुरा वाई पास सडक निकल चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलार्थी/वादी के विपरीत करने में भारी त्रुटि की है। उक्त रास्ता आराजी खसरा नम्बरान 486 व 489 तक पहुचता है और 30 फुट चौड़ाई में हमेशा से रहा है उसे राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा अक्स में अंकित नहीं होने के कारण उत्तरवादी मानने से उत्तरवादी का कोई संबंध नहीं है और धमकी रास्ते को बंद करने की दे रहे है जबकि उक्त रास्ते की भूमि उत्तरवादी का कोई संबंध नहीं है और न ही कभी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं 3 का निर्णय उत्तरवादी /प्रतिवादी के हक में निर्णित करने में भारी त्रुटि की है। धारा 80 सीपीसी के नोटिस से युक्ति प्रदान करने हेतु अपीलार्थी/वादी ने वादपत्र के साथ धारा 30(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर युक्ति प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर उत्तरवादी को तलव कर सुनवाई की है। इसलिए नोटिस की प्रकरणों में कोई आवश्यकता नहीं रही है। तनकी संख्या 4 का निर्णय उत्तरवादी के हक में करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि अपीलान्ट/वादी की आराजी के लिए आने जाने के लिए दूसरा विकल्प मौजूद है कतई गलत है ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है और न ही उत्तरवादी के द्वारा साबित किया गया है इसलिए भी निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय तहत कतई गलत है जो निरस्तनीय है। कथित रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से अपीलान्ट/वादी के रास्ते के लिए प्रस्तुत इस दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। न्यायालय को धारा 251 ए राजस्थान टी एक्ट के अनुसार राजस्व अभिलेख में नये सिरे से रास्ता कायम करने का पूर्णतया अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कारण दावा अपीलान्ट/वादी साबित करने में भारी त्रुटि की है जो रास्ता कायम कराया जा रहा है या अधीनस्थ न्यायालय को घोषित किया जाना है वह भूमि भी आम रास्ता (सरकार) की होगी। उससे उत्तरवादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। इसमें उत्तरवादी खेती को आने जाने के लिए उचित चौड़ाई में रास्ता कायम कराने का अपीलान्ट /वादी कृषक को कानूनी अधिकार प्राप्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कतई गलत एवं निरस्तनीय है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।



अधीनस्थ अपील प्रतियोगी
भरतपुर (राजस्थान)

2/4

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलव किया गया। पर्याप्त सूचना के बावजूद रेस्पोंडेन्ट्स हाजिर अदालत नहीं आये और न ही कोई वकील उनकी ओर से पैरवी हेतु उपस्थित हुआ।
3. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स को अपील पर सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दौराने बहस अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र की पत्रावली की ओर ध्यान आकर्षित कर दलील दी की अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा अन्तर्गत धारा 92 ए 88, 89, 188-251 (ए) आर.टी.एक्ट दिनांक 12.05.2017 को खारिज कर दिया जबकि अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 483, 484, 486, 487 वाके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतु 30 फुट चौड़ा कदीमी रास्ता हमेशा से हाल खसरा नम्बर 485, (जो सिवायचक भूमि है) की दक्षिणी मेंड के सहारे सहारे स्थित रहा है। जिसके उत्तरी भाग में होकर मथुरा वाईपास सड़क निकल चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय करने में भारी त्रुटि की है जो वादी के खिलाफ है। उक्त रास्ता आराजी खसरा नम्बर 486 व 489 तक पहुँचता है और 30 फुट चौड़ाई में रहा है। यह रास्ता राजस्व नक्शे में अंकित न होने से रेस्पोंडेन्ट्स ने नहीं माना। हमने धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी वादपत्र के साथ लगाया जिससे प्रकरण में नोटिस से छूट मिली। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता बताकर विवेचन किया है जबकि इन नम्बरो हेतु पहुँच का कोई रास्ता नहीं है। न्यायालय को धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नये सिरे से रास्ता कायम करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। हमारे खेतों तक पहुँच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। यदि दस गुणी पैनल्टी का भी आदेश फरमाते तो रास्ते हेतु हम यह शि जमा करवा देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालय की नजीरे यथा आरबीजे 2022 पेज 189, आर.आर.टी 2023(1) पेज 103, आर. आर.टी 2023 (1) पेज 486 उद्धृत की है। अतः हमारी अपील स्वीकार फरमायी जावे।
4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।
5. पत्रावली के अवलोकरण से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा आराजी ख0 नं0 483, 484, 486 व 487 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 485 में से रास्ता कायम करने की मांग की गई है। धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955 में प्रकरण के अतिआवश्यकता व कम दूरी के हिसाब से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा रास्ता चाहने वाले को वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध करना होता है इस प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रतिनिधि पैरोकार सरकार द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। जबाबदावा में हाल आराजी खसरा नम्बर 483, 484, 485 व 486 वाके ग्राम गोलपुरा के बीच स्थित मेंड पर राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता अंकित होना नहीं बताया। खसरा नंबर 485 के बाजानिब दक्षिण मेंड में कोई रास्ता अंकित नहीं बताया है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्सा में दर्ज न होने से दावा खारिज करने की प्रार्थना की। अपीलांट द्वारा न तो वादपत्र में एवं न ही अपील में हाल खसरा नम्बर 485 एवं उसके साबिक खसरा नम्बर 223 की जमाबन्दी पेश की गई है। हाल व गत खसरा नम्बर के नक्सों में कोई रास्ता अंकित/ दर्शित नहीं है। धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट में केवल निजी खातेदारों की भूमि में से ही रास्ता विधिक रूप से देने का प्रावधान है किन्तु हाल खसरा नम्बर 485 विसायचक भूमि की श्रेणी में आता है जिस पर रास्ता

देने हेतु धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और ऐसी राजकीय भूमि पर लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत ही रास्ता सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील आर.टी.एक्ट 1955 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और जो आदेश विचारण न्यायालय में पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्यों एवं इस प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने से उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं। इस प्रकार अपीलान्त की अपील निराधार व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपील फौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में मुज्राया गया।



(परशुराम धानका)

आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर